



धर्मेन्द्र कुमार

## भारत में सतत विकास के लिए शिक्षा: एक समीक्षा

आर. एल. महतो इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रामपुर, जलालपुर, दलसिंह सराय, जिला- समस्तीपुर, (बिहार), भारत

Received-01.06.2024, Revised-07.06.2024, Accepted-11.06.2024 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

**सांश्रः आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी कामों में से एक है। ग्रह पर मौजूद संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करना और साथ ही इस ग्रह पर रहने वाले इंसानों की भलाई सुनिश्चित करना। स्कूलों में शिक्षा को और ज्यादा प्रभावी और कुशल बनाने की स्पष्ट ज़रूरत है और इसके लिए, स्कूल समुदाय के हर हितधारक को स्थिरता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और समझना चाहिए कि आज के समय में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा सतत विकास की कुंजी है और स्कूलों और संस्थानों में सिर्फ 'सतत विकास' की अवधारणा के बारे में बात करने से हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। हम सभी को उठकर इस पर काम करना होगा, अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर। स्कूलों में पढ़ाई जा रही शिक्षा के हर पहलू पर फिर से नज़र डालने और उस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। स्कूलों के पाठ्यक्रम को वर्षों से सतत शिक्षा के नज़रिए से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यह लेख संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से, एसडीजी 4, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। लेखक ने सतत विकास और शिक्षा से संबंधित पहलुओं पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा की है, मौजूदा सिद्धांतों/मॉडलों के साथ-साथ अपने अनुभवों को भी इस शोधपत्र में साझा किया है तथा स्कूलों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन अच्छे तरीकों का उल्लेख करने का प्रयास किया है जिन्हें स्कूल, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान सतत विकास के लिए शिक्षा में अपना सकते हैं।**

**कुंजीश्रुत शब्द— सतत विकास, सतत विकास लक्ष्य, स्कूली शिक्षा, हितधारक, संवेदनशील, पाठ्यक्रम, स्कूल समुदाय।**

पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक अनिवार्य साधन है। शिक्षा के बिना किसी भी स्तर पर सतत विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बढ़ती आर्थिक प्रवृत्तियों और मानव के उपभोग पैटर्न के भीतर की प्रथाओं से स्पष्ट रूप से एक स्थायी भविष्य के लिए दूरदर्शिता की कमी दिखती है और इस चुनौती का समाधान करने के लिए, लोगों की जागरूकता, ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है और इसे शिक्षा को एक साधन के रूप में उपयोग करके किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की गई थी, जिसमें दुनिया भर के देशों ने भाग लिया और वैश्विक लक्ष्यों पर हस्ताक्षर किए। तब से, इन अत्यधिक निर्धारित महत्वाकांक्षी वैश्विक लक्ष्यों से संबंधित यह सवाल हर किसी के मन में रहा है। लोग सवाल करते रहे हैं, संदेह करते रहे हैं और बहस करते रहे हैं कि क्या ये लक्ष्य प्राप्त करने योग्य और प्रकृति में यथार्थवादी हैं। वर्ष 2000 से 2015 तक घोषित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के दौरान बहुत कुछ हासिल किया गया। लेकिन, कई खामियाँ थीं जो एमडीजी की विफलता का कारण बनीं और फिर SDG की घोषणा की गई, जिसमें दुनिया को 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य दिए गए और इसे एजेंडा 2030 कहा गया, जिसका आदर्श वाक्य था, 'कोई भी पीछे न छूटे' और इसलिए, MDG के कार्यान्वयन के दौरान की गई गलतियों को न दोहराना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सभी को उन गलतियों से सीखना है और कठ के कार्यान्वयन के दौरान डकल से प्राप्त सफलता को दोहराना है और स्पष्ट रूप से पहचानी गई गलतियों में से एक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं होना था। ऐसा नहीं है कि सतत विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास नहीं किए गए हैं, जिसे बड़े पैमाने पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ESD के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्कूलों में दी जा रही शिक्षा प्रति में सैद्धांतिक है और व्यावहारिक होने के बजाय किताबों में है। और इसे हम 'सतत विकास के आसपास की शिक्षा' कह सकते हैं। और दोनों शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक आपको सिखाता है कि सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है और दूसरा शब्द आपको बताता है कि आपको वास्तव में सतत विकास को लागू करने और प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई और कदम उठाने चाहिए। सतत विकास के लिए शिक्षा आपको इस ग्रह का एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाती है और इसका उद्देश्य एक ऐसा ग्रह बनाना है, जो सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और रहने योग्य हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।

**सामग्री और विधियाँ—** समीक्षा लेख सतत विकास के लिए शिक्षा विषय पर आलोचनात्मक और रचनात्मक विश्लेषण के साथ किया गया है। समीक्षा में पिछले मौजूदा साहित्य और अध्ययनों के रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण करने और वर्तमान परिस्थ में शोध अंतराल का पता लगाने की कोशिश की गई है और सुझाव दिया गया है कि क्या नया किया जा सकता है और आगे के शोध के लिए विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

पद्धतिगत दृष्टिकोण के संदर्भ में, कथात्मक प्रकार की समीक्षा का चयन किया जाता है। इसमें, कुछ मौजूदा साहित्य के परिणामों और निष्कर्षों की समीक्षा और चयनित विषय के वर्तमान और नवीनतम अवलोकन की प्रस्तुति लेखक के अनुभव के आधार पर होती है और गुणात्मक परिणामों को साझा और चर्चा की जाती है।

**लक्ष्य 4 –** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सतत विकास लक्ष्य 'सतत विकास लक्ष्य 4' (एसडीजी 4) सभी के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा की वकालत करता है, जो 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा', 'बाल अधिकारों पर सम्मेलन', 'सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा', 'कार्रवाई के लिए डकार रूपरेखा' और 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्य' सहित कई अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं में निहित है, और इस प्रकार



शिक्षा को व्यक्तियों, राष्ट्रों की मलाई के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

एसडीजी 4 का उद्देश्य सभी को सार्वभौमिक और समान शिक्षा प्रदान करना है और यह अन्य सभी 16 वैश्विक लक्ष्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। एसडीजी 4 'समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने' की वकालत करता है और इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं; यह सुनिश्चित करें कि सभी लड़कियों और लड़कों को 2030 तक निःशुल्क, समान और उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिले, जिसके परिणामस्वरूप प्रासंगिक और प्रभावी शिक्षण परिणाम प्राप्त हों।

यह सुनिश्चित करें कि सभी लड़कियों और लड़कों को 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बचपन विकास, देखभाल और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच हो ताकि वे प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार हो सकें, सुनिश्चित करें कि 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों को विश्वविद्यालय सहित सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी, व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच हो। 2030 तक शिक्षा में लैंगिक अंतर को दूर करें और सुनिश्चित करें कि विकलांग व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों और अनिश्चित परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों सहित कमजोर लोगों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच हो। सुनिश्चित करें कि 2030 तक सभी युवा और वयस्कों की एक महत्वपूर्ण संख्या, पुरुष और महिला दोनों, साक्षर और संख्यात्मक हो। सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षार्थी 2030 तक सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करें, जिसमें अन्य बातों के अलावा सतत विकास और टिकाऊ जीवन शैली, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना, वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक विविधता की सराहना और सतत विकास में संस्कृति का योगदान शामिल है।

**शिक्षा और संघारणीयता के बीच संबंध-** शिक्षा और संघारणीय विकास के बीच संबंध को समझना इतना आसान नहीं है। यह प्रकृति में जटिल है। किसी भी राष्ट्र की संघारणीय विकास लक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता शिक्षा की स्थिति और स्तर पर निर्भर करेगी। यह बुनियादी आवश्यकता है जिसे हम सभी को समझना होगा। इसके बिना, निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाएंगे। बिना किसी योजना के कोई भी लक्ष्य केवल एक इच्छा है और इसके अनुसार, एक राष्ट्र के रूप में हमें केवल कागजों में नहीं बल्कि कार्रवाई में एक शैक्षिक योजना और रणनीति की आवश्यकता है।

शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में लाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके, महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करके, पर्यावरण की रक्षा करके, सभी आयु समूहों को शिक्षा प्रदान करके, ड्रॉपआउट दरों को कम करके, आदि नागरिकों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।

**सतत विकास के लिए शिक्षा-** शिक्षा सतत विकास को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण घटक और मुख्य उपकरण है और इसलिए पिछले दो दशकों में सतत विकास के लिए शिक्षा के महत्व को दर्शाने और उसे बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएँ, सेमिनार और संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं।

2015 में घोषित किए जाने के बाद से ही एस जी डी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। एस जी डी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में जबरदस्त प्रयास और संसाधन लगाए गए। एस जी डी को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, यह है - लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और भागीदारी।

यह भी पहचाना गया कि नीति निर्माण प्रयासों और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, व्यवहार में बदलाव लाना और सतत विकास के बारे में और उसके प्रति जन जागरूकता लाना बहुत महत्वपूर्ण है। नतीजतन, शिक्षा और इसकी आउटरीच गतिविधियाँ जैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, संचार, सार्वजनिक जागरूकता, वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सूचना साझाकरण और पहुँच, नेटवर्किंग और सहयोग, अन्य के अलावा, एस जी डी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपरोक्त व्यवहार परिवर्तन के अलावा, एस जी डी को प्राप्त करने में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सतत विकास कार्यक्रमों के लिए कई शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और विश्वासों को बेहतर बनाना है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, प्रासंगिक समर्थन, सामाजिक मानदंड, कार्य कठिनाई और आदतन व्यवहार, अन्य बातों के अलावा, सभी ऐसे तत्व हैं जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

यदि लोगों के विचारों को बदलना है, तो शिक्षा को इससे आगे बढ़कर उन्हें उनके मूल्यों के अनुरूप तरीके से कार्य करने में मदद करनी चाहिए। अध्ययन ने यह दिखाने का प्रयास किया था कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से दृष्टिकोण और व्यवहार के बीच कमजोर संबंध हैं और स्कूलों में सतत विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को डिजाइन करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाल के दिनों में, शिक्षा का ध्यान 21वीं सदी के कौशल हासिल करने और उन्हें सुसज्जित करने पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि यदि किसी को शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों और शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के स्तर में सुधार करना है, तो यह अनिवार्य है। दुनिया तेजी से बदल रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम समय पर दुनिया और मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हैं, 21वीं सदी के कौशल की आवश्यकता है। कई चुनौतियों की पहचान की गई है, जैसे कि कम उम्र में स्कूल छोड़ना, युवा बेरोजगारी, अकुशल मानव शक्ति, नागरिकों का निरंतर पुनः कौशल विकास, शहरीकरण और बहु-सांस्कृतिक विसर्जन। ये 21 वीं सदी की चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूलों के शैक्षिक पाठ्यक्रम, शैक्षिक संसाधनों के प्रकार और हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे शैक्षणिक दृष्टिकोण को अद्यतन करना महत्वपूर्ण है।





**कोविड-19, शिक्षा और सतत विकास-** कोविड-19 ने हमें दिखाया कि देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोविड-19 के कारण ही दुनिया ने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में फिर से गहनता से सोचना शुरू किया है। दुनिया भर में और देश भर में स्कूल लगभग दो साल से बंद हैं। हम सभी ने पहले कभी इस तरह की दुनिया के बारे में नहीं सोचा था और न ही देखा था। स्कूल बंद होने से सीखने में बहुत बड़ी कमी आई है और इसे दूर करने में कुछ और साल लगेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है, जहाँ हम भारत में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की पहल और उपकरणों का उपयोग होते हुए देख सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बहुसंख्यक देश होने के कारण, यहाँ लाखों छात्र ऐसे हैं जिनके पास नेटवर्क, फ़ोन और कक्षाएँ नहीं हैं। यहाँ, पहले बुनियादी शिक्षा प्रदान करना आवश्यक हो जाता है और फिर शिक्षा के माध्यम से सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

सतत विकास की परिभाषाएँ भविष्य की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन भविष्य की जरूरतों के बारे में भूल जाइए, कोविड के दौरान और बाद की स्थिति से पता चलता है कि हमें नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी और इसलिए यह सवाल उठता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितने यथार्थवादी हैं जब हम कहते हैं कि एसडीजी को 2030 तक हासिल करना है। सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में कोविड-19 से सीख ले रहे हैं और खुद को सतत विकास के लिए तैयार कर रहे हैं।

**नई शिक्षा नीति और सतत विकास के लिए शिक्षा के प्रति इसका दृष्टिकोण-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई थी, जो 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति बन गई। नई शिक्षा नीति को सतत विकास के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है और उम्मीद है कि यह सभी को समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करके भारत को लक्ष्य 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाएगी। यदि भारत निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को समय पर प्राप्त करना चाहता है, तो नई शिक्षा नीति ने देश की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को संरचित करने की आवश्यकता पर विशेष विचार किया है।

नई शिक्षा नीति ने सतत विकास और जीवन, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण और जैविक संसाधनों की सुरक्षा, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों सहित व्यापक और एकीकृत पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। नई शिक्षा नीति ने विशेष रूप से सतत विकास के बारे में शिक्षक शिक्षकों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने पर जोर दिया है और पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य इस तरह से शिक्षा प्रदान करना है कि यह स्थायी आजीविका प्रदान करे और उत्पन्न करे और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे। एनईपी से पहले भी शिक्षा के माध्यम से सतत शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में ध्यान और प्रयास किए गए हैं। सतत विकास ढांचे के लिए प्रशांत शिक्षा ने औपचारिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान पहले ही कर ली है, ताकि उनके ज्ञान और समझ का निर्माण हो सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए सतत प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

सतत विकास के लिए शिक्षा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। चूंकि नई शिक्षा नीति हाल ही में पेश की गई है और नीति के संपूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। तब तक, राष्ट्र अच्छे तरीकों का पालन और कार्यान्वयन जारी रख सकता है, प्रयास कर सकता है कि कैसे नई शिक्षा नीति और सतत विकास के लिए शिक्षा घटक पाठ्यक्रम पद्धति का एक अंतर्निहित हिस्सा बन सकते हैं और इसे भारत के हर शैक्षणिक संस्थान में कैसे पहुँचा और लागू किया जा सकता है।

**सतत विकास के लिए शिक्षा में बाधाएँ-** इस तथ्य के बावजूद कि सतत विकास के लिए शिक्षा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रमुख फोकस रहा है, लेकिन अभी तक बहुत सीमित प्रगति देखी गई है। प्रगति की कमी में योगदान देने वाले कई कारक और कारण हैं। लेखक की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के ग्लोबल स्कूल एंबेसडर और अधिवक्ताओं के साथ वास्तविक समय की बातचीत, जिन्होंने स्कूलों और समुदायों में सतत विकास के लिए शिक्षा को लागू करने का काम किया है, भारत में सतत विकास के लिए शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण बाधाएँ और चुनौतियाँ हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

1. जागरूकता की कमी: ग्रामीण भारत के जमीनी स्तर के स्कूलों में काम कर रहे ग्लोबल स्कूल एडवोकेट्स के साथ व्यक्तिगत बातचीत के दौरान, यह पाया गया कि सतत विकास लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की सख्त जरूरत है। एसडीजी की घोषणा किए जाने के छह साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शिक्षक समुदाय अभी भी वैश्विक लक्ष्यों से अवगत नहीं है। शैक्षिक समुदाय के लिए जागरूक होना और यह महसूस करना जरूरी है कि पूरी शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा के पुनर्संरचना के बिना स्थिरता हासिल करना संभव नहीं है।

2. पाठ्यक्रम में सतत विकास के लिए शिक्षा का अभ्यास: यह स्पष्ट होना चाहिए कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्कूलों में पाठ्यक्रम में एक समान तरीके से सतत विकास के लिए शिक्षा कैसे लागू की जाएगी। राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सिर्फ किताबों में शामिल न हो और छात्र सतत विकास की अवधारणाओं के बारे में सीख रहे हों और इसे रट रहे हों। पाठ्यक्रम में सतत विकास के लिए शिक्षा का अभ्यास करने का अर्थ है, सतत विकास के लिए शिक्षा पर कार्य करना और सतत विकास के लिए शिक्षा की अवधारणा को रटना नहीं।

3. सतत विकास के लिए शिक्षा की अवधारणा को सरल बनाना: सतत विकास के लिए शिक्षा की अवधारणा को सरल बनाना आवश्यक है। कई शोध और अध्ययनों से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सतत विकास और इसकी जटिलता



को परिभाषित करने की कोशिश की है। सतत विकास के लिए शिक्षा की अवधारणा में जटिलता से मदद नहीं मिलेगी, इसे सरल बनाना होगा और इसे छोटे-छोटे कार्यों में बदलना होगा, जिन्हें स्कूल समुदाय समझ सके और लागू कर सके। यहां तक कि 17 एसडीजी लक्ष्य भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं और इसलिए छात्र समुदाय को यह समझाया जाना चाहिए कि कैसे हर छोटा कदम स्थिरता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। और जब देश और दुनिया भर में हर कोई ऐसे छोटे-छोटे कदम उठाएगा, तो स्थिरता हासिल करना संभव है।

4. सतत विकास के लिए शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी: सतत विकास के लिए शिक्षा को स्थानीय संदर्भ से देखना महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। स्थानीय भागीदारी के बिना सतत विकास के लिए शिक्षा की अवधारणा को लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। समुदाय के सदस्यों को पता होना चाहिए कि सतत विकास के लिए शिक्षा क्या है, स्कूलों में कौन सी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं और स्कूल समुदाय के विकास में कैसे योगदान दे रहा है।

5. साझा स्वामित्व, सहयोग और मजबूत भागीदारी का अभाव: कोई भी क्षेत्र यह नहीं कह सकता कि उसका सतत विकास से कोई लेना-देना नहीं है। हर विभाग, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, सतत विकास के लिए शिक्षा के प्रति समान रूप से जिम्मेदार है। सरकारों के मंत्रालयों और विभागों के बीच सहयोग की कमी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच कमजोर संबंध और भागीदारी और नागरिक समाज संगठनों के समावेश की कमी हमें सतत विकास के लिए शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन से रोकती है।

6. वित्तीय संसाधनों और सामग्रियों की कमी: यह सच है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित निधियों को खर्च कर रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर वास्तव में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, सामग्री और संसाधनों के निर्माण, पाठ्यक्रम विकास और संबंधित सामग्रियों में निवेश के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। वित्तीय बाधाओं के साथ, कार्रवाई और शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालिक रूप से स्थिरता को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण है।

**चुनौतियों पर काबू पाने और सतत विकास के लिए शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिणाम, चर्चा और सुझाव—**  
जागरूकता फैलाना: सतत विकास के लिए शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना पहला कदम होगा। अगर लोगों को यह नहीं पता कि स्थिरता और शिक्षा क्या है, दोनों के बीच क्या संबंध है, तो सही दिशा में आगे बढ़ना असंभव है।

सतत विकास के लिए शिक्षा का प्रभावी पाठ्यक्रम: सतत विकास के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्कूल समुदाय और हितधारकों के बीच सही दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहार विकसित करना होगा। इसे व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए और यह प्रकृति में सरल, सटीक और कार्रवाई योग्य होना चाहिए। सतत विकास के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थिरता से संबंधित गतिविधियाँ अंतर्निहित होंगी।

सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: पाठ्यक्रम तैयार करने वाले विशेषज्ञों के लिए स्थानीय संदर्भ और प्रासंगिकता पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति को अपनी बैठकों और योजनाओं में समुदाय के सदस्यों को शामिल करना चाहिए और इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय समुदाय स्कूल की गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकता है और स्थिरता की दिशा में योगदान दे सकता है।

संघारणीयता मंच: विद्यालयों में संघारणीय विकास के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मंचों, मंचों और समितियों का पुनर्गठन और उपयोग करने की आवश्यकता है। बाल संसद, बाल सभा, बाल कैबिनेट, विद्यालय प्रबंधन समिति आदि जैसे मंचों को संघारणीयता पर पूरे वर्ष कार्रवाई के साथ गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों जैसे सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी बढ़ेगी।

नेटवर्किंग, भागीदारी और सहयोग: सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों, संस्थानों और सभी संबंधित हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता है और संघारणीय विकास के लिए शिक्षा को लागू करने के लिए एक सामूहिक समूह बनने की आवश्यकता है। इससे क्षमता का निर्माण होगा और वित्तीय और संसाधन संबंधी बाधाओं को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

**निष्कर्ष—** शिक्षा, निस्संदेह, सतत विकास लाने की कुंजी है और एक गेम चेंजर टूल है। शिक्षा स्कूल समुदाय के बीच दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल में आवश्यक परिवर्तन ला सकती है, जो अंतिम भविष्य की समस्या समाधानकर्ता और निर्णय निर्माता बन सकते हैं। यदि स्कूल, संस्थान, कॉलेज व्यावहारिक तरीके से शिक्षा के केंद्रीय भाग के रूप में स्थिरता के विषय को ला सकते हैं, तो यह सतत विकास के लिए शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान होगा। इस पत्र में यह जांचने का प्रयास किया गया है कि सतत विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही क्या अध्ययन और साहित्य किए गए हैं, अच्छी प्रथाएँ साझा की गई हैं और अभी भी सतत विकास के लिए शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ और बाधाएँ क्या हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। समीक्षा लेख स्थिरता के आसपास आवश्यक कार्यों और कदमों को विस्तृत करने का प्रयास करता है और सतत विकास के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है न कि सतत विकास के बारे में शिक्षा पर।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मोहंती, ए., और दाश, डी. (2018). एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट: भारत के लिए सस्टेनेबल एजुकेशन का एक अवधारणात्मक मॉडल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, 7(9), 2242-2255.
2. बैंगे, सी. (2016). प्रोटेक्टिंग द यूथर: स्कूल एजुकेशन की भूमिका इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एन इंडियन केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन एंड ग्लोबल लर्निंग।



3. रविद्रनाथ, एम. जे. (2007). इंडिया में टीचर एजुकेशन में एनवायरनमेंटल एजुकेशन: अनुभव और चुनौतियाँ इन द यूनाइटेड नेशन्स डेकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जर्नल ऑफ एजुकेशन फॉर टीचिंग, 33(2), 191-206.
4. बंगा छोकर, के. (2010). इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हायर एजुकेशन एंड करिक्युलम इन्नोवेशन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन हायर एजुकेशन, 11(2), 141-152.
5. लिटल, ए. डब्ल्यू, और ग्रीन, ए. (2009). सक्सेसफुल ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 29(2), 166-174.
6. अलेक्सांडर, आर., और पोय्यामोली, जी. (2014). पुडुचेरी और कुड्डालोर क्षेत्रों, भारत से एक्टिव शिक्षण और सीखने पर आधारित स्थायी विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा की प्रभावशीलता – एक मामला अध्ययन। स्थायी शिक्षा के जर्नल, 7(1), 1-20.
7. चौधरी, एस. के. (2021). भारत में स्थायी विकास के लिए शिक्षा: एक कथात्मक अध्ययन।
8. फ्रेड्रिक्सन, यू, एन. कुसानागी, के., गौगोलाकिस, पी., मात्सुदा, वाई., और कितामुरा, वाई. (2020). स्थायी विकास के लिए शिक्षा (म्वे) के पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन: स्वीडन और जापान में। स्थायीता, 12(3), 1123.
9. मोहंती, ए., और दाश, डी. (2018). सतत विकास के लिए शिक्षा: भारत के लिए सतत शिक्षा का एक रूपांतरणात्मक मॉडल। अंतरराष्ट्रीय विकास और स्थिरता की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, 7(9), 2242-2255.
10. रुद्रप्रा, रोकोनो. (2022). नागालैंड, भारत में स्थायी विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने की बाधाएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, 10. 990-993. 10.21474/अश्र।101/14805.

\*\*\*\*\*